डिजीटल पत्र

दैनिक

कांग्रेस दर्पण

पटना, 19 जून, बुधवार, 2024

बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल सदाकत आश्रम पटना – 10

नरेद्र मोदी के नेतृत्व वाली यह एनडीए सरकार बहुत ही नाजुक :राहुल गांधी

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली यह एनडीए सरकार बहुत ही नाजुक है। उन्होंने कहा है कि अपने तीसरे कार्यकाल में एनडीए की सरकार अस्तित्व के लिए संघर्ष कर सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में, राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि 4 जून के फैसले के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। राहुल गांधी ने कहा, ₹संख्या इतनी कम है कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक हैं, और थोड़ी सी भी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है... सहयोगियों को दूसरी तरफ मुड़ना पड़ सकता है।₹

रायबरेली और वायनाड दोनों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने कहा, ₹यह विचार कि आप नफरत फैला सकते हैं, आप गुस्सा फैला सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं – भारतीय लोगों ने इस चुनाव में इसे खारिज कर दिया है।₹ राहुल गांधी ने कहा, ₹यही कारण है कि गठबंधन संघर्ष करेगा,₹ उन्होंने कहा कि ₹क्योंकि 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के लिए जिन चीज़ों ने काम किया वह काम नहीं कर रहा है।₹ लोकसभा चुनाव के नतीजों में विपक्ष के इंडिया ब्लॉक ने एग्जिट पोल की भविष्यवाणी से काफी बेहतर प्रदर्शन किया और 543 में से 234 सीटें हासिल कीं। जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटों पर जीत दर्ज की। इन नतीजों ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति में फिर से सबसे आगे ला दिया है। अनुमान है कि उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली लेकिन पिछले दो लोकसभा चुनाव की तरह इस बार बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। सरकार बनाने के लिए उसे अपने एनडीए के साथियों पर निर्भर होना पड़ा है।

वायनाड सीट खाली करेंगे राहुल, प्रियंका लड़ेंगी उपचुनाव: सोमवार को राहुल गांधी ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश में रायबरेली लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बरकरार रखेंगे और केरल में वायनाड सीट खाली करेंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस मुद्दे पर अटकलों को खत्म करते हुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके आवास पर चर्चा के बाद दोनों सीटों पर निर्णय की घोषणा की। बैठक में खड़गे और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा यह चुनाव जीतती हैं तो वह पहली बार सांसद के तौर पर संसद में प्रवेश करेंगी। यह भी पहली बार होगा कि गांधी परिवार के तीन सदस्य – सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका – एक साथ संसद में होंगे।

रेल मंत्री का इस्तीफा न देना लज्जाजनक, दुर्घटना की केंद्र ले जवाबदेही : डॉ0 संजय

रेलवे के खाली पड़े लाखों पदों पर शीघ्र भर्ती करे केंद्र सरकार

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास सोमवार को हुये भीषण रेल हादसे एवं मौतों की जवाबदेही लेते हुये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अब तक इस्तीफा न देना बीजेपी की लज्जाहीन राजनीति का परिचायक है। उक्त बयान बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉ० संजय यादव ने मिडीया से बातचीत में दिया। उन्होंने कहा कि इस रेल दुर्घटना की शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक ओर जहां रेलवे का तेज गति से निजीकरण किया जा रहा है, मोदी अपने कारपोरेट मित्रों के फायदे के लिये जनता के हित को दांव पर लगा रहे हैं। रेलवे सुविधाओं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। सरकार जनता के इस सबसे आरामदेह और सस्ते यातायात साधन को नष्ट करने में खुद ही जुटी है। रेल बजट

को भी मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। रेलवे की सुरक्षा के लिये जरूरी बातों पर सरकार आपराधिक लापरवाही बरत रही है। जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। रेल और जनता विरोधी इन्ही नीतियों का असर है कि रेल दुर्घटनाओं में तेजी आयी है। डॉ० संजय ने कहा कि मोदी सरकार में रेलवे भर्तियों में भारी कमी आयी है। बड़ी संख्या में रेलवे के जरूरी और तकनीकी पद खाली हैं। जिसका सीधा असर रेलवे संचालन और रेलवे सुरक्षा पर पड़ा है। बढ़ती दुर्घटनाओं का यह बड़ा कारण हैं। केंद्र सरकार को इन रिक्त पदों पर जल्दी ही भर्ती निकाले, जिससे एक ओर बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी, दूसरी ओर रेल संचालन बेहतर होने से रेल दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।

बिहार प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमिटी के सदस्य डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव ने देवेश चंद्र ठाकुर को भेजा लीगल नोटिस

कहा कि 10 दिनों के अंदर माफी मांगे नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

विधानपरिषद के पूर्व सभापति एवं सीतामढ़ी से सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर के आपत्ति जनक बयान पर उन्हें कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर कमिटी के सदस्य डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव ने कानूनी नोटिस भेजा है। श्री यादव ने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिशिर कुमार कौण्डिल्य के माध्यम से उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया है। इस बाबत देवेश चंद्र ठाकुर से कहा गया है कि वे अपने बयान के मद्देनजर 10 दिनों के भीतर बिहार की जनता से माफी मांगे अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। गौरतलब है कि डॉक्टर यादव पूर्व में भी इस प्रकार के आपत्तिजनक बयान देने के मद्देनजर कई सांसदों और मंत्रियों को कानूनी नोटिस भेज चुके हैं। इस बाबत कुछ मामले तो ऐसे रहे हैं, जिसमें इन्होंने मुकदमा भी किया है, और बाद में न्यायालय द्वारा माफी मंगवाने की प्रक्रिया भी हुई। इनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक बयान देने के मद्देनजर दो ऐसे मामले हुए, जिनमें दो सांसदों को सजा भी हुई। अभी हाल ही में डीएमके नेता दयानिधि मारन द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भी इन्होंने श्री मारन को कानूनी नोटिस भेजा था। हालांकि उन्होंने तब सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी। बहरहाल, इस बार फिर उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर को उनके आपत्तिजनक बयान के

लिए कानूनी नोटिस भेजा है और कहा कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की टिप्पणी किया जाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री यादव ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से पिछड़ा , अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के विषय में इंगित करते हुए श्री ठाकुर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए ।इस मामले उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर से कहा कि अपने बयान के मद्देनजर वे माफी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में आज खतरनाक ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत और 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इस हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और मोदी सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर से बेहद दुखी हूं, जहां कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'दुर्घटना के दृश्य दर्दनाक हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में, हम उनमें से प्रत्येक के प्रति अपनी एकजुटता और संवेदना व्यक्त करते हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही उन्होंने पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने की भी मांग की। खरगे ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में, मोदी सरकार रेल मंत्रालय के 'पूरी तरह से कुप्रबंधन' में लगी हुई है।

कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में, यह रेखांकित करना हमारा कर्तव्य है कि कैसे मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय को 'कैमरा-ड्रिविन' सेल्फ प्रमोशन के प्लेटफॉर्म में बदल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, 'आज की त्रासदी एक कड़वी सच्चाई की एक और याद दिलाती है।'

खरगे ने आगे कहा, 'कोई गलती न करें, हम अपने सवालों पर कायम रहेंगे और भारतीय रेलवे की इस घटना के लिए मोदी सरकार को जवाबदेह बनाएंगे।

10 साल बाद कांग्रेस लोकसभा में अपना विपक्ष का नेता बनाने जा रही है

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। 10 साल बाद कांग्रेस लोकसभा में अपना विपक्ष का नेता बनाने जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी (उहउ) की बैठक में राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने का आग्रह किया गया था। हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक अपने फैसले की सार्वजनिक जानकारी नहीं दी है। मगर इस बीच सोमवार को कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोचक वाकया देखने को मिला। जब राहुल गांधी ने बताया कि बात नहीं मानने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने धमकी दी। हालांकि, राहुल गांधी ने यह बात मजाकिया लहजे में कही। राहुल गांधी का यह अंदाज लोगों को खूब पंसद भी आ रहा है।

दरअसल, सोमवार को कांग्रेस ने राहुल गांधी के वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का एलान किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जानकारी दी कि वायनाड से प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी पार्टी की परंपरागत सीट रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से पूछा कि अपने कहा था कि अगर राहुल गांधी बात नहीं मानेंगे तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या ये आपकी बात मान रहे हैं?

रिपोर्ट के सवाल पर मल्लिकार्जुन खरगे कहते हैं कि यह आगे की बात है। मगर इस बीच मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि धमकी तो दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे धमकी दी है। इसके बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल हंसने लगते हैं।कांग्रेस कार्यसमिति ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय राहुल गांधी को दिया था और एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने का आग्रह किया था। मजाक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह भी कहा था कि अगर वह फैसले का पालन नहीं करेंगे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कार्यसमिति की बैठक में यह भी कहा था कि पार्टी नेताओं की राय और भावनाओं को देखते हुए राहुल गांधी को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि, राहुल गांधी ने अभी तक अपने फैसले की सार्वजनिक जानकारी नहीं दी है।

मुझे लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा हो, जिसका रेल से जुड़ाव ना हो, सुप्रिया श्रीनेत ने रेल हादसा पर भाजपा को घेरा

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। मुझे लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा हो, जिसका रेल से जुड़ाव ना हो। हम सब लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं और रेल से जुड़ी हुई बड़ी मधुर स्मृतियां हैं और रेल से ही कहीं ना कहीं आवागमन सबने, किसी ना किसी टाईम पर जरूर किया है। क्योंकि रेल सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनें नहीं हैं, दनदनाती हुई ट्रेनें नहीं हैं। रेल इस देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है, रेल हिन्दुस्तान की जीवन रेखा है और सबसे बड़ी बात है कि आवागमन का सबसे सस्ता, इकोनॉमिकल साधन है, एटलीस्ट हुआ करता था और उसी के कारण मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति रेल की यात्रा को प्रेफर करता है।

आज तक जब आप रेल में बैठते थे टिकट लेकर, तो कहीं ना कहीं यह विश्वास रहता था कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बड़े सारे स्टेशन आते थे, उसमें पूड़ी सब्जी खाई जाती थी, कहीं पर चाय पी जाती थी, कहीं पकौड़ी–समोसे खाए जाते थे और एक यह विश्वास था कि गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज जब रेल यात्री बैठता है, तो उसके मन में शंका रहती है कि गंतव्य तक वो पहुंचेगा या उसकी अर्थी और लाश पहुंचेगी, यह कीर्तिमान नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने स्थापित किया है।

मैं यहां पर आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। यह तस्वीर ठीक एक साल पहले इसी महीने जून की है, 02 जून, 2023 को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, करीब–करीब 300 लोगों की मौत हुई थी और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल में कल फिर एक ट्रेन हादसा हुआ। पटरी पर कंचनजंगा एक्सप्रेस थी, उसको पीछे से मालगाड़ी ने आकर मारा, 15 लोगों की मौत और अभी तक 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ठीक एक साल पहले बालासोर ओडिशा में और एक साल बाद पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा होता है। क्या बदला है एक साल में? आज पूछना पड़ेगा ना कि एक साल में क्या बदला है। लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं और मैं एक सरकारी आंकड़ा आपके साथ साझा कर देती हूं। 1,117 ट्रेन दुर्घटनाएं 2014 से 2023 तक और जान–बूझकर 2023 तक का ही आंकड़ा दे रही हूं। 31 मार्च 2023, क्योंकि यह हमारे आंकड़े नहीं हैं, आपके आंकड़े नहीं हैं, यह भारत सरकार के आंकड़े हैं। 1,117 ऐसी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जहां पर जान और माल का नुकसान हुआ है, यह सरकारी आंकड़ा है। असल आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा है।

मतलब हर महीने 11 ट्रेन हादसे हुए हैं, हर तीन दिन पर एक ट्रेन हादसा हो रहा है और उसमें जान और माल की क्षति हो रही है। तो क्या बदला एक साल में? इतना बड़ा बालासोर का ट्रेन हादसा हुआ, हम सबने लाशों का अंबार देखा, परिवारों को उजड़ते हुए देखा, छोटे–छोटे बच्चों को बिलखते हुए देखा। क्या बदला एक साल में? बालासोर से पश्चिम बंगाल, क्या बदला? क्या बदला 2014 से 2024 में? मैं एक सूची पढ़ देती हूं, आपको दिखा दिया है, लेकिन एक छोटी सी सूची है। 2014 में गोरखधाम एक्सप्रेस डीरेल हो जाती है, 25 लोगों की मौत हो जाती है। इंदौर–पटना एक्सप्रेस का हादसा होता है, 150 लोगों की मौत होती है। कैफियत एक्सप्रेस में 70 लोग घायल हो जाते हैं। पुरी–उत्कल एक्सप्रेस में 30 लोगों की मौत हो जाती है। बीकानेर–गुवाहाटी एक्सप्रेस में 36 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, 10 लोगों की मौत होती है। बालासोर, मैंने आपको बताया लगभग 300 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोग घायल

और कल 15 लोगों की मौत और 40 लोग घायल और मैंने यह सिर्फ कुछ आंकड़े बताए हैं, 1,117 ऐसे हादसे हुए हैं।

तो जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? इस देश में हमने वो भी मंत्री देखे हैं, अगर उनके डिपार्टमेंट में, अगर रेल मंत्री रहते हुए ऐसे हादसे हुए हैं, तो उन्होंने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। फिर वो लाल बहादुर शास्त्री हों, नीतीश कुमार रहे हों, माधवराव सिंधिया रहे हों, ममता बनर्जी रही हों, मधु दंडवते रहे हों, जॉर्ज फर्नांडिस रहे हों, सब लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है, लेकिन आज हिंदुस्तान का रेल मंत्री, रील मंत्री बना हुआ है। नैतिक जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, आज भी हादसे के वक्त रील कैसे अच्छी बनेगी, उस पर चर्चा हो रही है। बालासोर के वक्त अश्विनी वैष्णव वहां पर आए, डाईव कर रहे थे, ट्रेन के नीचे घुसकर झांक रहे थे, दो–चार टेसू बहा रहे थे। क्या किया आपने रेल को सुरक्षित करने के लिए? आप कल पहुंचते वहां पर, आप रेल मंत्री हैं, आप गाड़ी से भी जा सकते थे, लेकिन वीडियो ज्यादा बेहतर तब आएगा, जब आप जूम–जूम–जूम करके मोटरसाइकिल से जाएंगे। अच्छा वीडियो आ गया सामने, रील बना ली आपने, अब आप बताइए आपने एक साल से इस देश में रेल को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? उस रेल को सुरक्षित करने के लिए जिसमें इस देश का युवा, जिसमें किसान, जिसमें मजदूर, जिसमें मध्यम वर्ग अपने परिवारों के साथ चलता है, उसको सुरक्षित करने का क्या काम किया? लोगों के मन की आशंका है कि भैया हम पहुंचेंगे या हमारी लाश पहुंचेगी, उसको दूर करने का क्या काम किया?

कपिल सिब्बल ने एश्ट को लेकर बता दी विपक्ष की आगे की रणनीति

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक होने के खतरों को लेकर एक बार फिर से देश में बहर छिड़ गई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर एलन मस्क ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। इस बीच देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी ईवीएम मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा मैं इस मामले पर बाद में बोलूंगा, लेकिन अभी मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसका ईवीएम मुद्दे से कोई संबंध नहीं है और जिस तरह से चुनाव आयोग 2014 से व्यवहार कर रहा है, सभी विपक्षी दलों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाओं के इस तरह के रवैये से हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और विपक्ष को इसे आगामी सत्र में मजबूती से उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के चुनाव आयोग, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा है, विपक्ष इस पर कार्रवाई करेगा।

नालागढ़, देहरा और सुजानपुर पर उपचुनाव होने हैं, देहरा सीट से सीएम सुक्खू की पत्नी लड़ रही हैं चुनाव

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

शिमला। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को तीन विधानसभा सीटों (नालागढ़, देहरा और सुजानपुर) पर उपचुनाव होने हैं। जहां भाजपा ने तीन निर्दलीय उम्मीदवारों को उन्हीं की सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं, कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चुनाव में खास बात यह है कि इस बार देहरा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी चुनाव लड़ेंगी। आज उनके नाम का एलान हो गया है।

डबल एमए हैं कमलेश ठाकुरः कमलेश ठाकुर का जन्म सन् 1970 में हुआ था। उन्होंने इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई है। उनके पिता जी का नाम विचित्र सिंह व माता का नाम रोशनी देवी है। साल 1998 में उनकी शादी सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई थी। जो मौजूद समय में हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं।

कांग्रेस ने कमलेश पर क्यों खेला दांव?: देखें तो कमलेश का मायका जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र नलसूहा में है। लेकिन खास बात है कि यह गांव प्रशासनिक दृष्टि से देहरा उपमंडल के अंतर्गत आता है। ये कारण हो सकता है कि कांग्रेस ने कमलेश पर दांव खेला। वहीं सर्वेक्षणों में कमलेश का नाम भी सबसे आगे रहा है। ये वजह रही कि कांग्रेस हाईकमान ने इस बार कमलेश पर विश्वास जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। पिछले विधानसभा उपचुनाव में जनता ने दल-बदल की राजनीति को खारिज किया। ऐसे में संभावना है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिले। देहरा सीट कांग्रेस के लिए टेढी खीर है, ऐसे में कमलेश ठाकुर का इस सीट से खड़े होना सीएम सुक्खू के प्रभाव को जाहिर करेगा। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा ने जीत हासिल की थी। यह प्रयोग कांग्रेस देहरा में भी करना चाहती है।

कांग्रेस ने वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, पति रॉबर्ट वाड्रा ने बधाई दी

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। कांग्रेस ने वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। इस पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने बधाई दी है तो खुद के भी संसद पहुंचने की इच्छा एक बार फिर जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, 'प्रियंका गांधी मुझसे पहले संसद में होंगी। जब भी सही समय होगा, मैं भी उनके रास्ते पर आगे बढ़ सकता हूं। मैं खुश हूं और मुझे भरोसा है कि वायनाड की जनता उन्हें जीत दिलाएगी।' लोकसभा चुनाव से पहले भी कई बार रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। उन्होंने यूपी की मुरादाबाद और अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश तक की थी। लेकिन कांग्रेस ने उनके नाम पर विचार नहीं किया।

सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, 'मैं सबसे पहले देश की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिसने भाजपा को सबक सिखाया है। इन लोगों ने धर्म आधारित राजनीति की। मुझे खुशी है कि प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ने जा रही हैं। वह संसद में होंगी। उन्हें संसद में होना चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्होंने कैंपेन किया है बल्कि मैं भी ऐसा देखना चाहता हूं।' प्रियंका गांधी दशकों से कांग्रेस के लिए प्रचार करती रही हैं, लेकिन 2019 के आम चुनाव में वह सक्रिय राजनीति में आई थीं। उन्हें यूपी के एक हिस्से की जिम्मेदारी मिली थी। इस बार वह अमेठी और रायबरेली पर फोकस कर रही थीं।

वाड्रा ने कहा, 'प्रियंका गांधी को मुझसे पहले संसद में होना चाहिए। मैं भी सही समय पर उनके रास्ते पर बढ़ूंगा। मुझे खुशी है और उम्मीद है कि लोग उन्हें जिताएंगे।' वहीं अमेठी को लेकर अपनी दावेदारी पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, 'मेरे अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग देश भर के अलग-अलग हिस्सों से आ रही थी। लोग मेरे काम को समझते हैं और चाहते हैं कि इन्हें मौका मिले तो विकास में तेजी आए।' हालांकि कांग्रेस ने उनकी जगह पर वफादार माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा को उतारा, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री रहीं स्मृति इरानी को हरा दिया। वाड्रा को अमेठी से टिकट न मिलने पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें किनारे लगाया जा रहा है।

वायनाड छोड़ राहुल गांधी ने रायबरेली को ही क्यों चुना ? 5 पॉइंट में समझें कांग्रेस की रणनीति

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

लखनऊ। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में दो सीटों से लड़े थे। एक केरल की वायनाड सीट थी, तो दूसरी यूपी की रायबरेली सीट थी। दोनों सीटों पर राहुल गांधी को जीत मिली थी। सोमवार को राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब यहां पर उपचुनाव होगा। कांग्रेस की ओर से उप चुनाव में प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है। यह उनका राजनीतिक डेब्यू है, जिसको लेकर कांग्रेस अलर्ट हो गई है। आखिर राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली को ही क्यों चुना, जबकि वायनाड सीट पर 2019 में जीत मिली थी और अमेठी में हार गए थे, तो इसके पीछे कई सियासी मायने हैं।

खोई जमीन बनाने पर कांग्रेस का फोकस

उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के बाद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा, बल्कि यूपी की राजनीति में कई तरह की चर्चाओं का जन्म हुआ। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज एक सीट पर संतोष करना पड़ा था, तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी जद्दोजहद के बावजूद यूपी की सिर्फ दो विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ चुनाव लड़कर कांग्रेस ने छह सीटें जीती हैं, जिसके बाद यूपी में अपनी खोई हुई राजनीति को मजबूत करने में कांग्रेस जुट गई है।

यूपी में कांग्रेस ने बढ़ाई सक्रियता

वैसे कांग्रेस पार्टी की यूपी में सक्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता कि लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार यूपी में बेहद सक्रिय नजर आया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ सोनिया गांधी ने भी जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की। यहीं नहीं सोनिया ने अपने बेटे (राहुल गांधी) को रायबरेली की जनता को सौंपने की बात भी कही और बेटे के लिए प्रचार भी किया था। यूपी में मिली जीत के बाद से कांग्रेस ने यूपी में और सक्रियता बढ़ा दी है। जीत के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली में आभार सभा की। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव भी सपा के साथ मिलकर लड़ने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा होता है, तो कांग्रेस को यूपी में फिर संजीवनी मिल जाएगी। वहीं, अगर सपा की ओर से विधानसभा चुनाव में बात नहीं बनी, तो कांग्रेस उसकी तैयारी अभी से कर दी है।

1952 से रायबरेली पर गांधी परिवार का कब्जा

कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि राहुल गांधी ने उस सीट को चुना जहां से गांधी परिवार 1952 से जीतता आ रहा। रायबरेली से राहुल के दादा फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इंदिरा के पति फिरोज गांधी ने 1952 में पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की

थी। इंदिरा गांधी ने 1967 से 1977 के बीच 10 साल तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, 1977 में इंदिरा गांधी को हार मिली थी।

2004 से सोनिया ने संभाली रायबरेली की कमान

1980 में इंदिरा गांधी ने दो सीटों रायबरेली और अविभाजित आंध्र प्रदेश में मेडक से चुनाव लड़ा। दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ दी और मेडक को बरकरार रखा था। 1980 के बाद से गांधी परिवार के वफादार अरुण नेहरू, शीला कौल और कैप्टन सतीश शर्मा ने 2004 तक रायबरेली से जीत हासिल की। इनके बाद सोनिया गांधी यहां से लड़ती रहीं और 2019 तक यहीं से सांसद रहीं। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनिया ने इस सीट को राहुल के जिम्मे सौंपकर यहां से प्रतिधिनित्व करने का मौका दिया, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक विरासत रायबरेली, गांधी परिवार के लिए हमेशा से एक मजबूत गढ़ रहा है।

यूपी में बीजेपी को कड़ी चुनौती देना चाहते हैं राहुल

राहुल गांधी का यह कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत सियासी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि यह भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा संदेश है। यूपी, देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां की सियासत का राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव है। राहुल गांधी का यूपी में रहकर राजनीति करना बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है और इस मजबूती को 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जरिए तोड़ने की कोशिश करेगी। वहीं, परिवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी चाह रहे थे कि राहुल रायबरेली का प्रतिनिधित्व करें। इसके अलावा रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि परिवार ने अमेठी की खोई सीट भी हासिल कर ली। माना जा रहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यहा फैसला लिया गया है।

केरल के वायनाड के बजाय उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद रहना क्यों चुना, हम इसके पांच कारण आपको बता रहें हैं...

1) यूपी में खोई जमीन पाने की उम्मीद

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में छह सीटें जीतीं. 2019 में उसे सिर्फ रायबरेली सीट पर जीत मिली थी. इंडिया ब्लॉक ने यूपी में 43 सीटें जीतीं, जिनमें से 37 समाजवादी पार्टी ने जीतीं. यह एनडीए के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें जीती थीं. 2024 के चुनाव में, एनडीए सिर्फ 36 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी को 33 सीटें हासिल हुईं. वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी हार मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को हुई. इसका वोट शेयर 19% से घटकर 9% रह गया. ये वोट मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस को भी मिले। अगर एसपी ने बीएसपी के वोट शेयर का 6-7% हासिल किया, तो कांग्रेस को 2-3% का फायदा हुआ. कांग्रेस को उम्मीद है कि वह उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों का फायदा उठा सकती है. राहुल गांधी द्वारा वायनाड के बजाय रायबरेली सीट चुनने का पहला कारण यही नजर आता है.

2) रणनीति बदलाव और आक्रामक रुख

2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस ने अपना रुख बदल लिया है. राहुल गांधी का रायबरेली संसदीय सीट को बरकरार रहना और वायनाड सीट छोड़ना उस आक्रामक दृष्टिकोण का संकेत है. रशीद किदवई के मुताबिक, 'कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है. अब उसने रक्षात्मक से आक्रामक रुख अपनाया है. वायनाड एक रक्षात्मक दृष्टिकोण था. क्योंकि राहुल 2019 में अमेठी से अपनी संभावित हार को देखते हुए वहां पहुंचे थे. उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव नीतजों के देखकर ही राहुल ने वायनाड के बजाय रायबरेली को चुना है'.

राहुल गांधी वायनाड के सांसद के रूप में दक्षिण और प्रियंका उत्तर की कमान संभाल रही थीं, जो कांग्रेस की पुरानी रणनीति थी. इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम से सीख लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल ली है. किदवई कहते हैं, 'महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस को एक उम्मीद जगी है और इसके परिणामस्वरूप उसकी रणनीति में बदलाव आया है. यह सफल होगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा. भाजपा को चुनौती देनी है तो लड़ाई वहां लड़नी होगी जहां भगवा पार्टी वह मजबूत है न कि दक्षिण से. बीजेपी हिंदी हार्टलैंड में काफी मजबूत है. दक्षिण में वह अब भी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है. लेकिन अब तक बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई है.

3) देश में कांग्रेस के पुनर्जीवित होने के लिए यूपी जरूरी

कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है. इसलिए, जब क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के वोट बेस में सेंध लगाना शुरू किया, तो इसकी गिरावट सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखाई दी. केंद्र की सत्ता पर भी उसकी पकड़ ढीली होने लगी. अगर कांग्रेस को अपने दम पर केंद्र की सत्ता में आना है तो उसे खुद को उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित करना होगा. उत्तर प्रदेश में छह सीटें जीतना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है, भले ही उसे यह जीत समाजवादी पार्टी के साथ होने से मिली हो. कांग्रेस के लिए दूसरा अच्छा संकेत यह है कि जाट नेता जयंत चौधरी और उनके राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के एनडीए खेमे में होने के बावजूद, यूपी और हरियाणा में जाट वोटर पार्टी की ओर झुके हैं.

4) दिल जीतने के लिए, कांग्रेस को हार्टलैंड जीतना होगा

दिल जीतने के लिए कांग्रेस को हार्टलैंड जीतना होगा. यहीं पर उसे अकेले और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ गठबंधन में भाजपा से मुकाबला करना होगा. हार्टलैंड के नौ प्रमुख राज्यों में कांग्रेस को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा, क्योंकि लोकसभा की 543 में से 218 सांसद इन्हीं 9 राज्यों से पहुंचते हैं. कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी बेहतर प्रदर्शन किया है. रशीद किदवई कहते हैं, 'कांग्रेस हिंदी पट्टी में अपनी संभावनाएं तलाश रही है और इसीलिए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ाया जा रहा है'. यूपी में अधिक सीटें जीतकर, कांग्रेस बिहार में भी प्रभाव डाल सकती है, जहां वह राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ गठबंधन में है.

5) प्रियंका गांधी के वायनाड जाने से केरल भी सध जाएगा

केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे और कांग्रेस यहां सत्ता में आ सकती है. केरल की जनता या तो सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ या कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को चुनती आ रही है. राज्य की जनता ने 2021 में एलडीएफ को सत्ता में वापस लाकर अधिकांश राजनीतिक पंडितों को आश्चर्यचकित कर दिया. 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई (एम) का प्रदर्शन खराब रहा और उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली. कांग्रेस ने 2024 में 20 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी आईयूएमएल ने दो सीटें जीतीं. कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि चाहे राहुल गांधी ने वायनाड को बरकरार रखा हो या नहीं, केरल में 2026 में उसे जीत हासिल होगी. भाई राहुल की जगह प्रियंका गांधी के वायनाड से चुने जाने पर राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैम्पेन को भी गति मिलेगी. रशीद किदवई प्रियंका गांधी-वाड्रा के बारे में कहते हैं, 'केरल में, जहां 2026 में चुनाव होने हैं, प्रियंका की वायनाड में मौजूदगी से पार्टी को मदद मिलने की उम्मीद है'.

बिहार विभूति डा0 अनुग्रह नारायण सिंह की 136वीं जयन्ती के अवसर पर सदाकत आश्रम में आयोजित जयन्ती समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ Dr Akhilesh Prasad Singh जी ने चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें स्मरण और नमन किया। इस मौके पर उच्छ विधान परिषद Dr.Madan Mohan Jha þe, MLC Dr Samir Kumar Singh जी एवम् अन्य वरिष्ठ नेतागण मौजुद रहे।

फिर छिड़ा एग्ट पर विवाद, राहुल गांधी ने बाद जीतू पटवारी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए गंभीर आरोप

भोपाल। देश में लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद एक बार फिर एग्ट को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. इसको लेकर राहुल गांधी ने भी पहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने एग्ट को ब्लैक बॉक्स बताया और कहा कि भारत जैसे देश में किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है. इसके बाद सियासत तेज हो चली है. इस पूरे मामले को लेकर अब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सवाल उठाए हैं. जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा ₹एग्ट को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें तर्क के साथ तथ्य भी दिए जा रहे हैं. इसमें संदेह के बाद सबूत भी दिए जा रहे हैं! लेकिन इलेक्शन कमीसन ऑफ इंडिया अभी भी चुप है. जीतू ने आगे लिखा ₹क्या यह चुप्पी किसी बड़ी साजिश का कारण है?

एग्ट को लेकर लंबे समय से कांग्रेस सवाल खड़े करती नजर आई है. विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हर समय कांग्रेस ने एग्ट पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो कई बार इसको लेकर आंदोलन भी किया है. लेकिन, इस पूरे मामले पर एछडठ मस्क के पोस्ट के बाद राजनीति गर्मा गई है.

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ₹भारत में ई. वी. एम. एक ₹ब्लैक बॉक्स₹ है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है. हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं. जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है. और, धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है.

दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए. मनुष्यों या एआई द्वारा हैक होने का खतरा भले ही छोटा लगे, लेकिन यह अभी भी बहुत अधिक है.

आरएसएस की सहयोगी के तौर पर काम कर रही एनसीईआरटी, संविधान पर हमला कर रहीः जयराम रमेश

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन को लेकर विवाद के बीच, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि यह संस्था 2014 से आरएसएस की सहयोगी के रूप में काम कर रही है और संविधान पर हमला कर रही है।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने नीट–2024 परीक्षा में कृपांक (ग्रेस मार्क) विवाद के लिए एनसीईआरटी को जिम्मेदार ठहराया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल एनटीए की अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ''हालांकि यह सच है कि एनसीईआरटी अब पेशेवर संस्था नहीं रही। यह 2014 से आरएसएस से संबद्ध संस्था के रूप में काम कर रही है। अभी–अभी पता चला कि इसकी 11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की संशोधित पाठ्यपुस्तक में धर्मनिरपेक्षता के विचार की आलोचना की गई है।

रमेश ने कहा, ''एनसीईआरटी का काम किताबें प्रकाशित करना है, राजनीतिक पर्चे जारी करना या दुष्प्रचार करना नहीं।''

उन्होंने कहा, ''एनसीईआरटी हमारे देश के संविधान पर हमला कर रही है जिसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट रूप से भारतीय गणतंत्र के मूलभूत स्तंभ के रूप में दर्शाया गया है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा माना है।''

रमेश ने कहा कि एनसीईआरटी को याद रखना चाहिए कि ''यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, ना कि नागपुर या नरेन्द्र शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।''

कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया, ''आज इसकी सभी पाठ्यपुस्तकें संदिग्ध गुणवत्ता वाली हैं और मेरे स्कूल के दिनों से बिल्कुल अलग हैं।''

तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने भी एनसीईआरटी पर निशाना साधते हुए कहा, ''बेशर्म राजग 1.0 सरकार'' छात्रों से कुछ तथ्यों को छिपा रही है और दावा कर रही है कि ये तथ्य ''असहज करने वाले'' हैं।

उन्होंने कहा, ''इस तर्क के हिसाब से

तो बच्चों को विश्व युद्ध जैसे अन्य हिंसात्मक घटनाक्रम के बारे में क्यों पढ़ाया जाए।''

गोखले ने कहा, ''क्या भाजपा और मोदी को अपराधियों तथा दंगाइयों के रूप में अपने इतिहास पर शर्म आती है? छात्रों से सच क्यों छिपाया जाए ?''

स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को खारिज करते हुए एनसीईआरटी के निदेशक ने कहा कि पाठ्यपुस्तकों में गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद से संबंधित संदर्भों को बदला गया है क्योंकि दंगों के बारे में पढ़ाने से छात्र 'हिंसक और निराश नागरिक बन सकते हैं'।

एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने एक समाचार एजेंसी के संपादकों के साथ बातचीत में कहा कि पाठ्यपुस्तकों में बदलाव वार्षिक संशोधनों के तहत किए गए हैं और इन पर विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है।

सकलानी ने कहा, ''हमें स्कूली पाठ्यक्रमों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए? हम सकारात्मक नागरिकों का निर्माण करना चाहते हैं, ना कि हिंसक और दुखी लोगों का।''

उन्होंने कहा, ''जब वे बड़े होंगे तो इसके बारे में जान सकते हैं लेकिन स्कूली पाठ्यपुस्तकें क्यों ? जब वे बड़े हो जाएं तब उन्हें समझना चाहिए कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था।''

शिक्षा का निजीकरण कर रही है भाजपा सरकार : कुमारी सैलजा

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है।सुसैलजा ने बयान में कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं, पर सरकार रिक्त पदों पर भर्ती नहीं कर रही। इससे निजी स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये यह बड़ी समस्या बनती जा रही है क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे बच्चों को शिक्षा से वंचित रख कर उन्हें और ज्यादा पिछड़े रखना चाहती है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के 2300 स्कूलों में 9995 पीजीटी शिक्षकों के रिक्त हैं। इतने पद खाली होने से यह कहा जा सकता है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का षडयंत्र रचा हुआ है।

उन्होंने कहा कि यही स्थिति उच्च शिक्षा में बनी हुई है। प्रदेश के 182 कॉलेज में प्रोफेसर के 7986 में से 4618 पद खाली पड़े हैं। इन खाली पदों ने हरियाणा के भविष्य के रास्ते को संकरा एवं अंधकारमय बना दिया है।